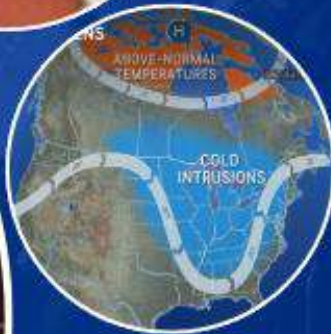


RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
जनवरी
10
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

रैट-होल माइनिंग / Rat-hole mining

संदर्भ:

हाल ही में असम के दीमा हासाओ जिले में एक कोयले की "रैट-होल" खदान में पानी भर जाने से कई मजदूर फंस गए थे।

रैट-होल माइनिंग क्या है?

परिचय:

- यह कोयला खनन की एक विधि है जिसमें संकीर्ण, क्षैतिज सुरंगें जमीन में खोदी जाती हैं।
- सुरंगें इतनी चौड़ी होती हैं कि केवल एक व्यक्ति रेंगकर कोयला निकाल सके।

प्रचलन और कारण:

- **स्थान:** पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, विशेष रूप से मेघालय और असम में प्रचलित।
- **कारण:** गरीबी, रोजगार के अन्य विकल्पों की कमी, और आर्थिक लाभ।
- पहाड़ी भू-भाग और कोयला भंडार की प्रकृति से पारंपरिक खनन कठिन हो जाता है।
- खनन कानूनों का कमजोर प्रवर्तन भी इसे बढ़ावा देता है।

प्रकार:

1. **साइड-कटिंग:** पहाड़ी ढलानों पर क्षैतिज सुरंगें खोदकर कोयला निकाला जाता है।
2. **बॉक्स-कटिंग:** आयताकार गड्ढे खोदकर कोयले तक पहुंच बनाई जाती है।

रैट-होल माइनिंग के कारण:

1. **आर्थिक कारक:**
 - गरीबी और रोजगार के अभाव में स्थानीय लोग इसमें शामिल होते हैं।
 - कोयला खनन से जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति।
2. **भूमि स्वामित्व:**
 - अस्पष्ट भूमि स्वामित्व कानून खनन को अवैध रूप से प्रोत्साहित करते हैं।
3. **कोयले की मांग:**
 - कोयले की निरंतर मांग, कानूनी और अवैध दोनों।
 - बिचौलिया और अवैध व्यापारी इसे बनाए रखते हैं।
4. **नीतिगत स्वामियां:**
 - कमजोर कानून और निरीक्षण।
 - विशेष प्रावधान जैसे नागालैंड में अनुच्छेद 371A खनन को नियंत्रित करने में बाधा।

रैट-होल माइनिंग की समस्याएं:

मानव सुरक्षा:

- संकीर्ण सुरंगों के ढहने का खतरा।
- खराब वेंटिलेशन से दम घुटने और विषाक्त गैसों का खतरा।
- सुरक्षा उपकरणों की कमी से दुर्घटनाएं और बीमारियां।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- **वन कटाई:** खनन के लिए पेड़ों का अंधाधुंध कटाव।
- **भूमि क्षरण:** अव्यवस्थित खुदाई से मिट्टी का कटाव।
- **जल प्रदूषण:** एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) से जल स्रोत दूषित।
- **वायु प्रदूषण:** कोयला जलाने और खराब वेंटिलेशन से।

सामाजिक समस्याएं:

- छोटे सुरंगों के कारण बाल श्रम का प्रचलन।
- स्थानीय समुदायों का विस्थापन और जीविका की हानि।

नियमन के उपाय:

कानूनी प्रवर्तन:

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** को सख्ती से लागू करें।
- अवैध खनन पर जुर्माना और उपकरण जब्त करें।
- नियमित निरीक्षण करें।

बाल श्रम उन्मूलन:

- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986** को सख्ती से लागू करें।
- शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और छात्रवृत्ति प्रदान करें।

सतत खनन प्रथाएं:

- वैज्ञानिक और यंत्रिक खनन विधियों को अपनाएं।
- पर्यावरणीय नुकसान को कम करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

एआई गवर्नेंस दिशा-निर्देश विकास पर रिपोर्ट / Report on AI governance guidelines development

संदर्भ:

एक सरकारी पैनल ने भारत के एआई मिशन के तहत एआई नियमों को लागू करने और भारत के तेजी से बढ़ते एआई परिस्थितिकी तंत्र के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति के गठन की सिफारिश की है।

AI Governance: AI गवर्नेंस का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं, मानकों, और दिशानिर्देशों से है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली और उपकरण सुरक्षित, नैतिक और निष्पक्ष हों। यह मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य उद्देश्य:

- सुरक्षा:** AI सिस्टम को ऐसे डिजाइन और तैनात करना, जो उपयोगकर्ताओं और समाज के लिए कोई खतरा न उत्पन्न करें।
- नैतिकता:** AI का विकास और उपयोग नैतिक मानकों के अनुरूप हो।
- निष्पक्षता:** AI एल्गोरिदम पूर्वाग्रह मुक्त हों और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करें।
- मानवाधिकार:** AI प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय गोपनीयता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना।

एआई गवर्नेंस पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

1. एआई गवर्नेंस के मूल सिद्धांत:

- पारदर्शिता:** एआई सिस्टम के विकास और उनकी क्षमताओं की प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- जवाबदेही:** एआई सिस्टम के डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं को उनके प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- सुरक्षा और विश्वसनीयता:** एआई सिस्टम को मजबूत, विश्वसनीय और सुरक्षित डिजाइन किया जाना चाहिए।
- गोपनीयता और सुरक्षा:** डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- न्याय और गैर-भेदभाव:** एआई को गैर-भेदभावपूर्ण और समानता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
- मानव-केंद्रित मूल्य:** एआई को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
- समावेशी नवाचार:** एआई नवाचार के लाभ समान रूप से वितरित किए जाने चाहिए।
- डिजिटल गवर्नेंस:** इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

2. लाइफ साइकिल दृष्टिकोण:

- नीति-निर्माताओं को एआई सिस्टम के विकास, उपयोग, और प्रसार के प्रत्येक चरण में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट जोखिमों को संबोधित करना चाहिए।
- "इकोसिस्टम दृष्टिकोण" के तहत एआई से जुड़े सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए।

3. प्रौद्योगिकी-सक्षम डिजिटल गवर्नेंस:

- एआई गवर्नेंस के लिए एक ऐसा तंत्र प्रस्तावित किया गया है जो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके इन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करे।

मुख्य सिफारिशें:

- अंतर-मंत्रालयीय एआई समन्वय समिति की स्थापना:**
 - विभिन्न मंत्रालयों और नियामकों के बीच एआई शासन का समन्वय करने के लिए।
 - इसमें MeitY, नीति आयोग, RBI, SEBI, और अन्य क्षेत्रीय नियामकों के प्रतिनिधि शामिल हों।
- तकनीकी सचिवालय का गठन:**
 - एआई समन्वय समिति के लिए एक तकनीकी सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करे।
- तकनीकी-कानूनी उपायों का उपयोग:**
 - डीपफेक से निपटने के लिए वॉटरमार्किंग और कंटेंट प्रोवेनेंस जैसी तकनीकी समाधानों का उपयोग करें।
- एआई घटना डेटाबेस स्थापित करें:**
 - वास्तविक एआई-संबंधित जोखिमों और हानियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए।
 - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें।

भारत में एआई का नियमन:

- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023:**
 - सरकार ने 2023 में यह अधिनियम पारित किया, जो एआई प्लेटफॉर्म से संबंधित गोपनीयता चिंताओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।
- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI):** भारत GPAI का सदस्य है।
 - 2023 का GPAI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां विशेषज्ञों ने जिम्मेदार एआई, डेटा गवर्नेंस, कार्य का भविष्य, नवाचार, और वाणिज्यीकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
- राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति:**
 - नीति आयोग द्वारा बनाई गई इस रणनीति में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, "स्मार्ट" शहरों और बुनियादी ढांचे, तथा स्मार्ट गतिशीलता और परिवर्तन पर अनुसंधान और विकास दिशानिर्देश शामिल हैं।
- जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत:**
 - फरवरी 2021 में नीति आयोग ने "जिम्मेदार एआई के सिद्धांत" शीर्षक से एक पेपर जारी किया, जिसमें भारत में एआई समाधान लागू करने से संबंधित नैतिक विचारों का विवरण दिया गया।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता / Nitrogen Use Efficiency

संदर्भ:

शोधकर्ताओं ने यह प्रदर्शित किया है कि पौधों में नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) के स्तर को कम करने से चावल और अरेबिडोप्सिस में नाइट्रोजन अवशोषण और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) की भूमिका:

- नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स को नियंत्रित करके नाइट्रेट अवशोषण को प्रभावित करता है।
- NO के निम्न स्तर उच्च-संबद्धता नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स (HATS) को सक्रिय करते हैं, खासकर सीमित नाइट्रोजन स्थितियों में।

फाइटोग्लोबिन का अतिप्रकाशन:

- फाइटोग्लोबिन, एक प्राकृतिक NO स्कैवेंजर, के अतिप्रकाशन से HATS (जैसे NRT2.1 और NRT2.4) की अभिव्यक्ति बढ़ती है, जिससे निम्न NO स्तरों पर नाइट्रोजन का अधिक प्रभावी अवशोषण होता है।

प्रोटीन नाइट्रोसाइलेशन:

- प्रोटीन नाइट्रोसाइलेशन, जो NO द्वारा प्रोटीन का जैव रासायनिक संशोधन है, नाइट्रोजन नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस प्रक्रिया को लक्षित करके नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) के परिणामों में सुधार हुआ है।

NO स्कैवेजिंग फॉर्म्यूलेशन:

- विभिन्न कृषि परिस्थितिक तंत्रों के लिए अनुकूल NO स्कैवेजिंग फॉर्म्यूलेशन का विकास नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग में कमी में सहायक हो सकता है।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) में सुधार का महत्व:

- नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना।
- पर्यावरणीय प्रदूषण, जैसे नाइट्रेट लीचिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, को कम करना।
- फसल उत्पादन में वृद्धि करना।

नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) के बारे में:

परिभाषा: यह पौधों द्वारा लागू या निश्चित नाइट्रोजन का जैव द्रव्यमान उत्पादन के लिए उपयोग करने की दक्षता को दर्शाता है।

- इसे फसल उत्पादन और मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित या बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडल से फिक्स किए गए नाइट्रोजन की मात्रा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

महत्व:

- NUE फसल प्रजनन कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण गुण है।
- इसका उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना है, साथ ही उर्वरकों जैसे इनपुट लागत को कम करना और नाइट्रोजन को पर्यावरण से बाहर रखना।

Nitrogen use efficiency (NUE)

$$NUE = N_{\text{Grain}} / N_{\text{Fertilizer}}$$

$$NUE = 1$$

- No loss to environment



3. पारंपरिक विधियों से जुड़ी समस्याएँ:

- NUE को बढ़ाने के लिए आमतौर पर अकार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।
- ये विधियाँ प्रभावी होने के बावजूद कई समस्याएं उत्पन्न करती हैं:
 - कृषि लागत में वृद्धि:** उर्वरकों का उपयोग किसानों के लिए परिचालन लागत बढ़ाता है।
 - पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - उर्वरक उत्पादन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के उत्सर्जन से प्रदूषण।
 - उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि।

नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) का महत्व

1. पौधों में विभिन्न प्रक्रियाओं का नियमन:

- NO पौधों में कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. नाइट्रोजन अवशोषण में भूमिका:

- NO उच्च-संवेदनशील नाइट्रेट परिवहनकों (High-Affinity Nitrate Transporters) को सक्रिय करता है।
- यह विशेष रूप से कम नाइट्रोजन स्थितियों में नाइट्रोजन के अवशोषण के लिए आवश्यक है।

पोलर वॉर्टेक्स / Polar Vortex

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका भीषण शीतकालीन तूफानों का सामना कर रहा है, क्योंकि आर्कटिक से ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) दक्षिण की ओर फैल रहा है, जिससे तापमान -50°C (-60°F) तक गिर रहा है।

पोलर वॉर्टेक्स के बारे में:

परिभाषा:

पोलर वॉर्टेक्स एक बड़ा निम्न दबाव और ठंडी हवा का तंत्र है, जो पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास बना रहता है।

- यह हमेशा ध्रुवों के पास रहता है, सर्दियों में मजबूत और गर्मियों में कमजोर होता है।
- "वॉर्टेक्स" का मतलब है वायु का घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाह, जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास सीमित रखता है।

पोलर वॉर्टेक्स के प्रकार:

1. क्षोभमंडलीय पोलर वॉर्टेक्स (Tropospheric):

- यह सबसे निचली वायुमंडलीय परत (10-15 किमी तक) में पाया जाता है, जहां अधिकांश मौसम की घटनाएं होती हैं।

2. समतापमंडलीय पोलर वॉर्टेक्स (Stratospheric):

- यह उच्च ऊंचाई (15-50 किमी) पर पाया जाता है।
- यह शरद ऋतु में सबसे मजबूत होता है और गर्मियों में गायब हो जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

उत्तरी गोलार्ध का वॉर्टेक्स:

- दो मुख्य केंद्र:
 1. बैफिन द्वीप, कनाडा।
 2. उत्तर-पूर्वी साइबेरिया।

दक्षिणी गोलार्ध का वॉर्टेक्स:

- आमतौर पर दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित।
- यह उत्तरी वॉर्टेक्स की तुलना में मजबूत और स्थिर होता है, जिससे इसका अस्थिर होना कम संभव है।

पोलर वॉर्टेक्स के कारण:

स्थिर स्थिति (Stable State):

- सामान्य परिस्थितियों में, पोलर वॉर्टेक्स मजबूत और आर्कटिक सर्कल के भीतर सीमित रहता है, जिससे ठंडी हवा ध्रुवीय क्षेत्रों तक सीमित रहती है।

कमजोर स्थिति (Weakened State):

- जब निचली वायुमंडलीय परत से गर्म हवा उठती है, तो यह पोलर वॉर्टेक्स के घूर्णी प्रवाह को विघटित कर देती है, जिससे आर्कटिक हवा दक्षिण की ओर फैलने लगती है।

कमजोर स्थिति में योगदान करने वाले कारण:

1. महत्वपूर्ण मौसम पैटर्न (जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं)।
2. उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रणालियों या समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव।
3. जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से ध्रुवों पर असमान गर्मी का प्रभाव, जो पोलर वॉर्टेक्स को कमजोर करता है।

पोलर वॉर्टेक्स के प्रभाव:

1. **अत्यधिक ठंडे तापमान** - मध्य अक्षांशों में अत्यधिक ठंडे तापमान की स्थिति बनती है।
2. **दीर्घकालिक शीत लहरें** - यह जीवन की सामान्य गतिविधियों को बाधित कर सकती हैं और आधारभूत संरचनाओं पर दबाव डाल सकती हैं।
3. **बर्फबारी में वृद्धि** - जैसे- पूर्वी यू.एस., कनाडा और यूरोप के कुछ हिस्सों में अधिक बर्फबारी होती है।
4. **ऐतिहासिक उदाहरण (2013-14)** - पोलर वॉर्टेक्स ने रिकॉर्ड-तोड़ बर्फबारी और लेक मिशिगन पर 93.3% बर्फीले आवरण का कारण बना।
5. **फसलों को Frost क्षति** - विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक ठंड का अनुभव नहीं होता, फसलों को नुकसान हो सकता है; बुवाई या कटाई में देरी हो सकती है।

नदी जोड़ो अभियान, पर्यावरणीय आपदा का स्रोत / River interlinking, the source of environmental disaster

संदर्भ:

25 दिसंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना:

1. परियोजना का उद्देश्य:

- इस परियोजना में "पन्ना टाइगर रिजर्व" के भीतर एक बांध का निर्माण शामिल है, जिससे पर्यावरणीय डूब क्षेत्र को लेकर चिंताएँ उठ रही हैं।
- यह परियोजना केन नदी (जिसे अधिशेष जल वाली माना जाता है) को जल-सम्पन्नता की कमी वाली बेतवा नदी से जोड़ेगी।

नदियों को जोड़ने का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- **शुरुआत:** 130 वर्ष पहले सर आर्थर कॉटन ने पहली बार बेसिन-आधारित जल हस्तांतरण की परिकल्पना की।
- **विस्तार:** इसे आगे एम. विश्वेश्वरैया द्वारा परिष्कृत किया गया।
- 1970 और 1980 के दशक में के.एल. राव और कैरन दिनशाँ जे. दस्तूर ने इस अवधारणा को "नेशनल वाटर ग्रिड" नाम दिया।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA):

- 1982 में NWDA की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 30 पहचाने गए नदी प्रणालियों की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था।
- परियोजनाओं की अनुमानित लागत: ₹5.5 लाख करोड़ (सामाजिक, पर्यावरणीय और परिचालन लागत को छोड़कर)।

नदी जोड़ परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव:

1. पारिस्थितिक तंत्र का विघटन:

- बांधों और नहरों के निर्माण से संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, के जलमग्न होने और जैव विविधता पर खतरे की संभावना।
- स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित।

2. जल विज्ञान में परिवर्तन:

- नदियों का प्रवाह मोड़ने से भूजल पुनर्भरण घटता और डेल्टा क्षेत्रों में लवणता बढ़ती है।
- उदाहरण: सिंधु डेल्टा में ऐसी समस्याओं से कृषि और आजीविका प्रभावित।

3. पारिस्थितिक सेवाओं का नुकसान:

- नदियाँ तट पर गाद लाने, पोषक तत्वों के चक्रण और आवास समर्थन जैसी सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव।
- नदियों की जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की भूमिका की उपेक्षा।

वैश्विक उदाहरणों से सीख:

- सिंधु डेल्टा (पाकिस्तान):** जल प्रवाह मोड़ने से जैव विविधता में गिरावट और पारिस्थितिक क्षति।
- सरदार सरोवर बांध (नर्मदा नदी):** आधुनिक भारतीय उदाहरण जो पर्यावरणीय क्षरण का संकेत देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मामले:**
 - **फ्लोरिडा नदी (फ्लोरिडा):** नदी के चैनलाइजेशन से पर्यावरणीय नुकसान।
 - **अरल सागर:** जल प्रबंधन की विफलता के कारण जल स्रोत का विनाश।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- विस्थापन और आजीविका का नुकसान:** परियोजनाओं से भूमि और घरों का डूबना, जैसे कि दाऊधन बांध से 9,000 हेक्टेयर भूमि का डूबना, कई गांवों को प्रभावित करेगा।
- पानी की असमानता:** सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य के बावजूद, कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने से असमानता बढ़ सकती है।
- आर्थिक निर्भरता:** स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं इन बड़ी परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भर हो सकती हैं, जो पर्यावरणीय क्षरण या परियोजना विफलता की स्थिति में टिकाऊ लाभ नहीं दे पाएंगी।

आगे का रास्ता:

- सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा:**
 - सामुदायिक भागीदारी के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) लागू करें।
 - ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करें।
 - वर्षा जल संचयन जैसी स्थानीय विधियों को अपनाएं।
- पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव अध्ययन को प्राथमिकता:**
 - नदी जोड़ परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का व्यापक अध्ययन करें।
 - जैव विविधता, आजीविका और डेल्टाई पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा सुनिश्चित करें।

भोजन का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ संघर्ष / The right to food and the struggle with the PDS

संदर्भ:

उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, नौकरशाही की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सूची से बाहर कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हालिया समस्याएं:

1. लाभार्थियों का बाहर होना:

- **झारखंड और ओडिशा** (2023) की रिपोर्ट में बताया गया कि बड़ी संख्या में परिवारों को PDS सूची से हटा दिया गया, जिससे कमजोर वर्ग खाद्यान्न से वंचित हो गए।

2. बिहार में संकट:

- बिहार भी PDS से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे हाशिए पर बसे समुदायों को किफायती खाद्यान्न की उपलब्धता में बाधा आ रही है।

बिहार में मुसहर समुदाय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें:

1. **आपूर्ति संकट:** कोविड-19 महामारी के कारण राशन की आपूर्ति स्थिर नहीं रही।
2. **राशन कार्ड समस्याएं:** कई मुसहर परिवारों के पास सक्रिय राशन कार्ड नहीं हैं या कार्ड अधूरे हैं।
3. **बायोमेट्रिक सत्यापन समस्याएं:** तकनीकी गलतियों के कारण कई लोग PDS सूची से हटा दिए जाते हैं, जिससे उन्हें नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है।
4. **राशन की गुणवत्ता और मात्रा:** FPS डीलर अक्सर निर्धारित राशन से कम मात्रा प्रदान करते हैं, और चावल की गुणवत्ता बहुत खराब होती है, जो अक्सर सबसे निचली श्रेणी का होता है।

PDS नामांकन के लिए दस्तावेज़ीकरण से संबंधित चुनौतियाँ:

1. आवेदन प्रक्रिया:

- बिहार में कागजी रूपों में आवेदन करते समय आधार वितरण की आवश्यकता होती है।
- ऑनलाइन आवेदन में जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।

2. कानूनी आधार:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) या PDS नियंत्रण आदेश (2015) के तहत इन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- अधिकारियों द्वारा इस दस्तावेज़ीकरण को डिजिटाइज्ड सिस्टम में एक oversight माना जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावशीलता:

खाद्य पहुंच और कवरेज:

- PDS लगभग 57% आबादी को कवर करता है और रियायती दरों पर चावल और गेहूं जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ प्रदान करता है।
- यह आर्थिक संकटों के दौरान एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। COVID-19 महामारी के दौरान इसने करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया।

रिसाव और भ्रष्टाचार:

- लगभग 28% आवंटित खाद्यान्न लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे भारी नुकसान होता है।
- भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की अवैध हेराफेरी व्यापक है। पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन जैसे तकनीकी उपायों के बावजूद रिसाव की समस्या बनी हुई है।

पोषण सुरक्षा:

- PDS मुख्य रूप से चावल और गेहूं जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है, लेकिन व्यापक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है। दाल और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे आवश्यक पोषण तत्वों की कमी कुपोषण से निपटने में इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है।

PDS सुधार के लिए आवश्यक कदम:

1. **दस्तावेज़ीकरण में सरलता:** अनावश्यक दस्तावेज़ हटाकर पात्र परिवारों तक पहुंच बेहतर बनाना।
2. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** नियमित ऑडिट और सामुदायिक निगरानी से भ्रष्टाचार पर काबू पाना।
3. **पोषक तत्वों की आपूर्ति:** खाद्य विविधता बढ़ाकर पोषण सुधारना, जैसे तमिलनाडु का मॉडल।
4. **डिजिटलीकरण और शिकायत निवारण:** डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत शिकायत प्रणाली से दक्षता बढ़ाना।

भारत- तालिबान पहली उच्च-स्तरीय वार्ता / India- Taliban first high-level talks**संदर्भ:**

दुबई में हुई बैठक ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत और तालिबान के बीच अब तक के सबसे उच्चस्तरीय संवाद को चिह्नित किया। हालाँकि भारत ने तालिबान प्रशासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह काबुल में एक छोटा मिशन संचालित करता है, जो व्यापार, सहायता, और चिकित्सा समर्थन के साथ-साथ मानवीय सहायता जारी रखता है।

भारत की तालिबान के साथ पहली उच्च-स्तरीय वार्ता:

विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की।

- यह तालिबान शासन के साथ भारत की पहली उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है।
- पहले भारत केवल संयुक्त सचिव स्तर पर तालिबान से संपर्क कर रहा था।

मुख्य चर्चा के क्षेत्र:**1. सुरक्षा चिंताएँ:**

- भारत ने अफगान भूमि पर भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) पर चिंता व्यक्त की गई।
- अफगान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने और समर्थन देने का आश्वासन दिया।

2. विकास और मानवीय सहायता:

- भारत ने अफगानिस्तान में चल रही मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन का वादा किया।
- भारत ने पहले ही खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, टीके और भूकंप राहत सामग्री सहित बड़ी मात्रा में सहायता भेजी है।
- स्वास्थ्य सेवाओं और शरणार्थी पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सहायता पर सहमति हुई।

3. चाबहार बंदरगाह का उपयोग:

- अफगानिस्तान में व्यापार और मानवीय सहायता के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति हुई।
- भारत को इस बंदरगाह के उपयोग के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली है।

4. खेल संबंध मजबूत करना:

- क्रिकेट में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
- भारत ने नोरडा में अफगान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएँ प्रदान करने का समर्थन किया।

भारत-अफगानिस्तान संबंध:**पृष्ठभूमि:**

- **1950 का मैत्री संधि समझौता:** भारत और अफगानिस्तान ने करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे।
- **तालिबान का लौटना:** भारत ने आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन संपर्क जारी रहे।
- **भारतीय दूतावास में तकनीकी टीम की तैनाती:** मानवीय सहायता और अफगान जनता से निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए।
- **आधिकारिक बैठक (नवंबर 2024):** काबुल में, तालिबान के रक्षा नेतृत्व और भारतीय राजनयिक के बीच पहली आधिकारिक बैठक।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व:**1. स्थान:**

- अफगानिस्तान का 'एशिया का हृदय' के रूप में स्थान ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- खैबर और बोलन दर्रे के माध्यम से भारत के लिए यह प्राचीन काल से मार्ग प्रदान करता रहा है।

2. स्थिरता और सुरक्षा:

- अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा सुरक्षित अड्डे के रूप में किया गया है।
- रचनात्मक जुड़ाव आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर सकता है।

3. मध्य एशिया के साथ जुड़ाव:

- अफगानिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर स्थित है, जो क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है।

4. भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना:

- मानवीय सहायता, जैसे 2021 में अफगानिस्तान में सूखा प्रभावित लोगों को गेहूँ की आपूर्ति, भारत की छवि को सुधारने में मदद करती है।

5. भारतीय परियोजनाएँ: अफगान-भारत मैत्री बांध (सलमा डैम), ज़ारंज-डेलाराम राजमार्ग, जैसे प्रमुख विकास परियोजनाएँ भारत की भागीदारी को दर्शाती हैं।

6. चीन की बढ़ती भूमिका

- चीन ने काबुल में शहरी विकास परियोजनाओं की पहल की है और राजदूतों के बीच आदान-प्रदान को तेज किया है।
- यह भारत के लिए क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने का एक रणनीतिक दबाव बनाता है।

कैशलेस ट्रीटमेंट योजना / Cashless treatment plan

संदर्भ:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार पहल शुरू की है।

कैशलेस ट्रीटमेंट योजना: एक परिचय

योजना का उद्देश्य:

कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। यदि दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जाती है, तो सरकार 7 दिनों तक के इलाज का खर्च वहन करेगी। इस पहल का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों की वित्तीय परेशानी को कम करना है।



योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. इलाज का खर्च:

- ₹1.5 लाख तक की सहायता 7 दिनों के इलाज के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जाए।
- हिट एंड रन मामलों में:** मृतकों के परिवार को ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

2. कार्यान्वयन एजेंसी:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस योजना को लागू करने में पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।
- e-Detailed Accident Report (eDAR)** एप्लिकेशन इस योजना के क्रियान्वयन में NHA की मदद करेगा।

3. कवरेज:

- यह योजना सभी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।



योजना की आवश्यकता और महत्व:

1. सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति:

- वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं से 1.80 लाख लोगों की मृत्यु दर्ज की गई।
- इनमें 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण और 10,000 बच्चों की मृत्यु शैक्षणिक संस्थानों के आसपास हुई।

2. समग्र कवरेज:

- इस योजना को सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर लागू करना समावेशित सुनिश्चित करता है और जीवनरक्षक उपायों की पहुंच बढ़ाता है।

3. प्रभावी कार्यान्वयन:

- प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय और उन्नत IT सिस्टम का उपयोग पहुंच को बेहतर बनाता है और प्रशासनिक देरी को कम करता है।

4. आर्थिक सहायता:

- हिट-एंड-रन मामलों में मुआवजा और इलाज के खर्च को कवर करना पीड़ितों और उनके परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करता है।

दीनदयाल बंदरगाह / Deendayal Port

संदर्भ:

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने दीनदयाल पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹57,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली प्रमुख पहलें घोषित की हैं।



दीनदयाल बंदरगाह के बारे में:

स्थान:

- गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित।
- पहले इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था।

रणनीतिक महत्व:

- भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक।
- उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार को संभालने में सहायक।
- मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण।

स्थापना:

- 1950 के दशक में निर्मित।
- 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में नाम बदला गया।

प्रकार:

- ज्वारीय (टाइडल), कृत्रिम बंदरगाह।
- थोक, तरल, और कंटेनर माल को संभालने में सक्षम।

ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर):

- विभिन्न प्रकार के माल के लिए उन्नत टर्मिनल।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ):

- भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- उद्योगों को आकर्षित करने और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

संदर्भ:

सिंगापुर ने फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 227 में से 195 देशों की यात्रा कर सकते हैं।

भारत की रैंकिंग:

2025 रैंक:

- 85वां स्थान।
- 57 देशों में वीजा-फ्री पहुंच।

हालिया रुझान:

- 2021 में 90वें स्थान से सुधार कर 2024 में 80वें स्थान पर पहुंचा।
- 2025 में 85वें स्थान पर गिरावट।

Henley Passport Index 2025:

Singapore leads in 2025's most powerful passports; India drops to 85th

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024:

परिचय:

- दुनिया के पासपोर्ट्स की मूल और अधिकारिक रैंकिंग।
- बिना वीजा के पहुंच योग्य स्थलों पर आधारित।
- 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन्स इंडेक्स (HVRI) के रूप में शुरू हुआ।

डेटा और कवरेज:

- 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल।
- पासपोर्ट का वीजा-फ्री 'स्कोर' उन देशों की संख्या से तय होता है, जहां वीजा के बिना पहुंचा जा सकता है।

प्रामाणिकता:

- अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) और हेनले एंड पार्टनर्स के अनुसंधान पर आधारित।
- पासपोर्ट रैंकिंग और वैश्विक गतिशीलता का मानक संदर्भ उपकरण।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI

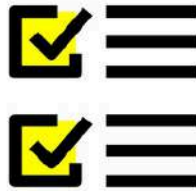


RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION

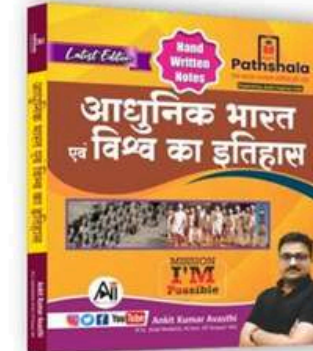
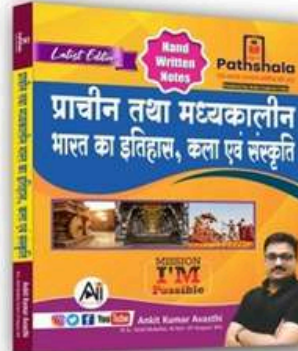
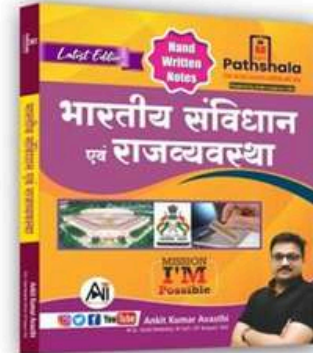
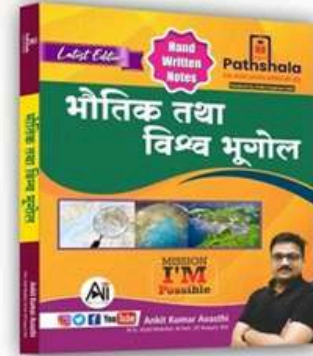
Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

 DAILY LIVE CLASSES

 WEEKLY TEST

 CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

 LIVE DOUBT SESSIONS

 DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

